



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 27 जनवरी, 2004/7 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2004

संख्या एल० एल० आर०डी (6)-29/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-01-2004 को यथा अनुमोदित हिमाचल

प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 19) को वर्ष 2004 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2004 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के जीवन के वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ ।

(2) यह 22 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे हमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 2 का
संशोधन ।

"(13) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;"

3. मूल अधिनियम की धारा 9-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 9-ख
का जोड़ना ।

"9-ख. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति.—राज्य सरकार, अपने किन्हीं अधिकारियों या अधिकरण द्वारा, जैसा यह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त-प्रबन्धन से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसका परीक्षण करने के पश्चात्, रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को हटाए जाने सहित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) में अन्तर्निष्ठ हैं और कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करेगा ।"

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

धारा 12 का
संशोधन ।

(i) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4-क) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकेगा,—

(क) जहां, इस धारा की उप-धारा (5) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है ; या

- (ख) जहाँ, कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है ; या
- (ग) जहाँ किसी दण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या
- (घ) जहाँ उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़ या गवाहों पर असर डालना) ।

(4-ख) निलम्बित कुलपति छुट्टी सम्बलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे कुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का, यदि यह ऐसे छुट्टी सम्बलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा:

परन्तु जहाँ निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्तर्वी किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा :—

- (i) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम की उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, बढ़ीतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोग्य नहीं है ;
- (ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोग्य है ; और
- (iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी ।

(4-ग) उप-धारा (4-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक की कुलपति यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है ।” ; और

(ii) उप-धारा (5) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 9-ख के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 12-ग रखा जाएगा, अर्थात् :—

का
संशोधन ।

“(7) कुलपति आपात स्थिति में जिसमें उन शक्तियों, जो उसमें निहित नहीं हैं, की बाबत तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, कारणों को अभिलिखित करके ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और मामले को ऐसे प्राधिकरण, जो ऐसी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो, के समक्ष इसकी ठीक आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखेगा न कि साठ दिन के पश्चात्, ऐसा न होने पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाएगी :

परन्तु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, किसी पोजीशन या समनुदेशन पर कोई नियुक्ति करने या किसी पदधारी को ऐसी पोजीशन या समनुदेशन में हटाए जाने के लिए नहीं किया जाएगा ।” ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12-घ में, —

धारा 12-घ
का संशोधन ।

(i) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(4-क). कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रतिकुलपति को निलम्बित कर सकेगा,—

- (क) जहां इस धारा की उप-धारा (5) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है; या
- (ख) जहां, कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है; या
- (ग) जहां किसी दण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या
- (घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आणकित छेड़छाड़ या गवाही पर असर डालना) ।

(4-ख). निम्नलिखित प्रतिकुलपति छुट्टी सम्बलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे प्रतिकुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का, यदि यह ऐसे छुट्टी सम्बलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा :

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चान्वर्ती किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा :—

- (i) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम की उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक

न हो, बढ़ीतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति को आरोप्य नहीं है ;

(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति को आरोप्य हैं, और

(iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी।

(4-ग) उप-धारा (4-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिकुलपति यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।” ; और

(ii) उप-धारा (5) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 9-ख के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु प्रतिकुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् मुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।”।

धारा 15
का प्रति-
स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“15. रजिस्ट्रार.—(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो विश्वविद्यालय के न्यायालय, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार उन अधिकारियों में से, जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम 5 वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम 9 वर्ष का सेवाकाल हो, राज्य सरकार द्वारा, ऐमा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।”।

धारा 16
का प्रति-
स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“16. वित्त अधिकारी.—(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का पदेन-सदस्य सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाओं (सामान्य शाखा) के अधिकारियों में से, जो नियन्त्रक की पंक्ति के नीचे के न हों, राज्य सरकार द्वारा, ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (v) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 21
का संशोधन।

“(v) रजिस्ट्रार: सदस्य-सचिव।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 35-क
का जोड़ना।

“35-क. पदों इत्यादि का सृजन.—विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।”।

11. (1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

2003 के
अध्यादेश
संख्यांक 7
का निरसन
और व्या-
वृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No 4 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT)
ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2004)

AN
ACT*further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970
(Act No. 17 of 1970).*BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the
Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—Short title
and
commence-
ment.1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh University
(Amendment) Act, 2003.(2) It shall be deemed to have come into force on the 22nd day of
September, 2003.Amend-
ment of
section 2.2. In section 2 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (herein-
after referred to as the "principal Act"), after clause (12), the following
clause shall be added, namely:—“(13) “State Government means the Government of Himachal
Pradesh;”.Addition of
section 9-B.3. After section 9-A of the principal Act, the following section shall
be added, namely:—

“9-B. *Power of State Government to enquire.*—The State Govern-
ment may, cause an enquiry to be made by any of its officers
or agency, as it may direct on any matters connected with the
administration and finances of the University or the institutions
maintained by it and the report of such enquiry shall be sent
to the State Government and the State Government after exam-
ining the same, shall forward the report to the Chancellor
and may also recommend any action including removal of Vice-
Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may be, if in
its opinion there exist such circumstances as are contained in
sub-section (5) of section 12 of this Act and the Chancellor may
take action accordingly:

Provided that before taking such action, the Chancellor shall
afford a reasonable opportunity of being heard to the Vice-
Chancellor or Pro-Vice-Chancellor, as the case may be.”.

Amend-
ment of
section 12.

4. In section 12 of the principal Act,—

(i) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added,
namely:—“(4-a). The Chancellor, by general or special order, may place
the Vice-Chancellor under suspension,—(a) where an enquiry under sub-section (5) of this
section is contemplated or is pending ; or

- (b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University ; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial ; or
- (d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(4-b). The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:—

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor ;
- (ii) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor ; and
- (iii) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clauses (i) and (ii).

(4-c). No payment under sub-section (4-b) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.”; and

- (ii) at the end of sub-section (5), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 9 or section 9-B of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.”.

Amend-
ment of
section
12-C.

5. In section 12-C of the principal Act, for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

“(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reason in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice-Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect:

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment.”.

Amend-
ment of
section
12-D.

6. In section 12-D of the principal Act,—

(i) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely :—

“(4-a). The Chancellor, by general or special order, may place the Pro-Vice-Chancellor under suspension,—

- (a) where an enquiry under sub-section (5) of this section is contemplated or is pending; or
- (b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or
- (d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tampering with documents or to influence witnesses).

(4-b). The Pro-Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Pro-Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :—

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the

period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Pro-Vice-Chancellor ;

(ii) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Pro-Vice-Chancellor; and

(iii) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clauses (i) and (ii).

(4-c). No payment under sub-section (4-b) shall be made unless the Pro-Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.”; and

(ii) at the end of sub-section (5), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 9 or section 9-B of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Pro-Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.”.

7. For section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 15.

“15. Registrar.—(1) There shall be a Registrar who shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Court, the Executive Council and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of the University, the Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the officers who have put in at least five years service in the Indian Administrative Services or at least nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services, under the State Government, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provisions of the First Ordinance of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be prescribed by the Statutes.”.

8. For section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 16.

“16. Finance Officer.—(1) There shall be Finance Officer who shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the Finance Committee of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of University, the Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch), not below the rank of Controller, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provision of the First Ordinance of the University.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes."

Amend-
ment of
section 21.

9. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (iv), the following clause (v) shall be added, namely:—

"(v) Registrar : Member-Secretary."

Addition of
section
35-A.

10. After section 35 of principal Act, the following shall be added, namely:—

"35-A. *Creation of posts etc.*—No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government."

Repeal of
Ordinance
No. 7 of
2003 and
savings.

11. (1) The Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.